बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
23 जुलाई 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 180
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

एक और पेपर लीक!

परीक्षा से पहले छात्रों तक पहुचे सवाल!

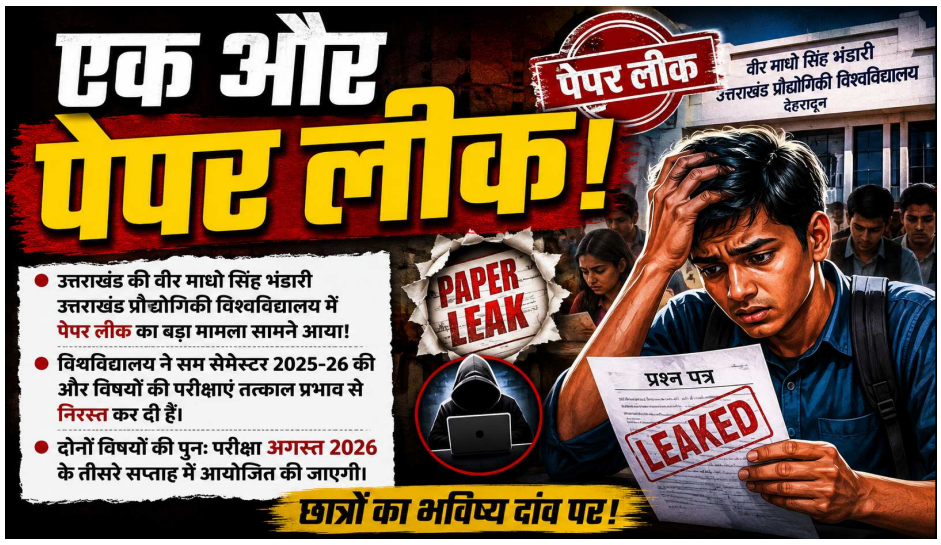

संवाददाता

देहरादून। परीक्षा से पहले छात्रों तक सवाल पहुंचने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दो पेपर रद्द कर दिये हैं।

आज यहां उत्तराखंड की वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक का बड़ा मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय ने सम सेमेस्टर 2025-26 की और विषयों की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी हैं। दोनों विषयों की पुनः परीक्षा अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र से संबंधित सामग्री छात्रों तक पहुंचने और परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता भंग होने की पुष्टि के बाद यह निर्णय लिया गया है। मामले में संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिवालिक कालेज आफ इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता पर सात वर्षों के लिए विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय की परीक्षा को लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा से पहले छात्रों तक प्रश्न साझा किए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय ने उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन किया। वहीं संबंधित संस्थान शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून ने भी अपने स्तर पर आंतरिक जांच कराई। विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय जांच समिति और संस्थान की आंतरिक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि संबंधित विषय के बाह्म प्रश्न पत्र आशीष कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देहरादून ने परीक्षा से पहले छात्रों के आंतरिक पोर्टल और व्हाट्सएप के माध्यम से परीक्षा से संबंधित समान प्रश्न साझा किए थे। विश्वविद्यालय ने इसे परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता, शुचिता और अकादमिक मानकों का गंभीर उल्लंघन माना है।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मैकेनिकल लर्निंग फार इंटरनेट आफ थिंग्स विषय का प्रश्नपत्र भी उसी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया था। विश्वविद्यालय ने आशंका जताई कि इस विषय की परीक्षा की गोपनीयता भी प्रभावित हो सकती है। इसी कारण छात्रहित और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दोनों विषयों की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कुलपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विषय कोड और की पूर्व में आयोजित परीक्षाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। दोनों विषयों की री-एग्जाम अगस्त 2026 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी।

विश्वविद्यालय ने बताया कि पुनः परीक्षा की विस्तृत और परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द ही विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। सभी संबद्ध संस्थानों के निदेशकों और प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रभावित छात्र-छात्राओं को तत्काल इस निर्णय की जानकारी दें, ताकि वे समय रहते पुनः परीक्षा की तैयारी कर सकें। साथ ही सभी संस्थानों को इस अधिसूचना को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वविद्यालय ने मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए आशीष कुमार गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, शिवालिक कॉलेज ऑफ

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

युवाओं के गुस्से से हिला 'सिस्टम'

कार्यालय संवाददाता

नई दिल्ली। देशभर में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और युवाओं के बढ़ते आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि पेपर लीक के दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के इस बयान को सरकार की ओर से युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, प्रधानमंत्री के इस ऐलान के कुछ ही समय बाद कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से पहली राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। संगठन ने कहा कि केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। असली चुनौती परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और दोषियों तक कार्रवाई पहुंचाने की है। पार्टी के नेताओं ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं। लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ, लेकिन अधिकांश मामलों में कार्रवाई लंबी खिंचती रही। ऐसे में यदि फास्ट ट्रैक कोर्ट वास्तव में समयब(सुनवाई कर दोषियों को सजा दिलाते हैं तो इसका स्वागत किया जाएगा।

संगठन का कहना है कि युवा अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि परिणाम चाहते हैं। यदि परीक्षा माफिया और उनके राजनीतिक संरक्षण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तो नई व्यवस्था भी केवल कागजों तक सीमित रह सकती है। अपने बयान में कहा कि पेपर लीक का सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, बल्कि इससे युवाओं का पूरे भर्ती तंत्र पर भरोसा कमजोर होता है।

संगठन के अनुसार लाखों अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करते हैं, आर्थिक और मानसिक दबाव झेलते हैं, लेकिन एक पेपर लीक पूरे परिश्रम पर पानी फेर देता है। ऐसे में दोषियों को शीघ्र सजा के साथ-साथ प्रभावित अभ्यर्थियों को समयबद्ध न्याय भी मिलना चाहिए।

सीजेपी ने सरकार से मांग की कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के साथ-साथ परीक्षा

◆पीएम मोदी ने फेंका फास्ट ट्रैक का पासा, पर क्या रुक पाएगी धांधली
◆फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान, लेकिन विपक्ष को अब भी दिखता है झोल

प्रणाली में भी व्यापक सुधार किए जाएं। संगठन ने सुझाव दिया कि परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय हो। डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनाई जाए। पेपर तैयार करने से लेकर वितरण तक हर चरण की निगरानी हो। परीक्षा माफिया और उनके नेटवर्क की राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो। भर्ती परीक्षाओं का निश्चित कैलेंडर बनाया जाए ताकि युवाओं का समय बर्बाद न हो।

प्रधानमंत्री का यह ऐलान ऐसे समय आया है जब देशभर में पेपर लीक का मुद्दा लगातार राजनीतिक बहस के केंद्र में है। विपक्ष लगातार सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अब सख्त कानूनी कार्रवाई का संदेश देने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर सीजेपी इस मुद्दे को केवल कानून-व्यवस्था नहीं बल्कि युवा अधिकार और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के सवाल के रूप में पेश कर रही है। संगठन का मानना है कि यदि सरकार इस बार ठोस कार्रवाई करती है तो युवाओं का विश्वास दोबारा बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री के ऐलान और सीजेपी की प्रतिक्रिया के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक का मुद्दा अभी राजनीतिक विमर्श से बाहर नहीं होने वाला। संसद से लेकर सड़कों तक इस पर बहस जारी रहने की संभावना है। सरकार अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाना चाहती है, जबकि विपक्ष और छात्र संगठन इस बात पर नजर रखेंगे कि घोषणा जमीन पर कितनी तेजी से लागू होती है और क्या वास्तव में दोषियों को समयबद्ध सजा मिलती है।

पेपर लीक अब केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है। यह देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, सरकार की विश्वसनीयता और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जांच एजेंसियां कितनी निष्पक्षता और तेजी से काम करती हैं, अभियोजन कितना प्रभावी होता है और अदालतों में मामलों का निस्तारण वास्तव में समयबद्ध हो पाता है या नहीं। युवाओं की नजर अब घोषणा पर नहीं, बल्कि उसके परिणाम पर टिकी है।

दून वैली मेल

संपादकीय

सवाल पूरे देश में गूंज रहे

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता की आवाज होती है। लेकिन जब उस आवाज का जवाब लाठियों से दिया जाए और लाठी चलाने वालों में वर्दीधारी पुलिस के साथ-साथ सादे कपड़ों में मौजूद लोग भी दिखाई दें, तो सवाल सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं रह जाता सवाल लोकतंत्र की विश्वसनीयता का बन जाता है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सामने आए कई वीडियो और तस्वीरों ने देशभर में बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोग प्रदर्शनकारियों पर डंडे चलाते और पुलिस के साथ कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। इन दृश्यों को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि ऐसे दावे सही हैं, तो यह बेहद गंभीर विषय है और यदि दावे गलत हैं, तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज करना भी उतना ही जरूरी है। खामोशी किसी भी स्थिति में समाधान नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस के हाथ में लाठी इसलिए दी जाती है कि वह कानून का पालन कराए, न कि कानून और भीड़ के बीच की रेखा ही मिट जाए। अगर भीड़ को नियंत्रित करना था, तो वर्दीधारी पुलिस पर्याप्त थी। फिर सवाल उठना स्वाभाविक है कि सादे कपड़ों में सक्रिय दिख रहे लोग कौन थे? क्या वे अधिकृत पुलिसकर्मी थे? क्या वे किसी विशेष ड्यूटी पर थे? यदि हां, तो उनकी पहचान और भूमिका स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही? और यदि नहीं, तो किसी नागरिक को कानून हाथ में लेने की अनुमति किसने दी? दुर्भाग्य यह है कि हाल के वर्षों में हर बड़े आंदोलन के बाद मूल मुद्दा पीछे छूट जाता है और बहस पुलिस बनाम प्रदर्शनकारी तक सिमट जाती है। लेकिन जंतर-मंतर की घटना ने एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया है क्या अब लोकतांत्रिक आंदोलनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऐसे चेहरे इस्तेमाल किए जाएंगे जिनकी कोई आधिकारिक पहचान ही न हो? अगर ऐसा है तो यह केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं की परीक्षा है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन संस्थाओं पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। यही लोकतंत्र की असली पूंजी है। यदि किसी कार्रवाई पर संदेह पैदा हो जाए और सरकार या पुलिस समय रहते तथ्यों के साथ स्थिति स्पष्ट न करे, तो अफवाहें ही सच का स्थान लेने लगती हैं। लोकतंत्र में पारदर्शिता विकल्प नहीं, अनिवार्यता है। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस प्रशासन की है। यदि सादे कपड़ों में दिख रहे लोग पुलिस बल का हिस्सा थे, तो यह स्पष्ट किया जाए कि वह किस इकाई से थे और किस आदेश के तहत तैनात थे। यदि वह पुलिसकर्मी नहीं थे, तो उनकी पहचान सार्वजनिक की जाए और यह बताया जाए कि वह हिंसक गतिविधियों में कैसे शामिल हुए। किसी भी निष्पक्ष जांच में वीडियो फुटेज, सीसीटीवी रिकार्डिंग, बाडी कैमरा और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल किए जाने चाहिए। लोकतंत्र में संदेह का उत्तर दमन नहीं, बल्कि सत्य होता है। जंतर-मंतर केवल दिल्ली का एक चौराहा नहीं है। यह वह जगह है जहां देश के किसान, जवान, छात्र, कर्मचारी, महिलाएं और आम नागरिक वर्षों से अपनी मांगें लेकर आते रहे हैं। यदि वही स्थान लोगों में भय का प्रतीक बनने लगे, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज देश का नागरिक एक सीधा सवाल पूछ रहा है जंतर-मंतर पर लाठी किसने चलाई? इस सवाल का जवाब किसी राजनीतिक बयान से नहीं, बल्कि तथ्यों और पारदर्शी जांच से मिलना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब पैदा होता है जब जनता को यह भरोसा ही न रहे कि कानून केवल वर्दी पहनकर चलता है। यदि सच्चाई साफ है, तो उसे सामने आने दीजिए। यदि कोई दोषी नहीं है, तो जांच से डर कैसा? और यदि कोई दोषी है, तो उसकी पहचान चाहे जितनी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून का सामना उसे ही करना चाहिए। लोकतंत्र की असली ताकत यही है कि यहां सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि नागरिक का अधिकार है।

खुले में कूड़ा जलाने पर 25000 रुपए का जुर्माना लगेगा

संवाददाता

उत्तरकाशी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में आज जिला कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला अधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि खुले में कूड़ा जलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा वा लापरवाही पर अधिकारियों की जिम्मेदारी वा जवाबदेही तय होगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कचरा प्रबंधन राष्ट्रीय प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी निकायों और पंचायतों को सोर्स सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण अधि

नियम शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बल्क वेस्ट जनरेटर्स का पंजीकरण, मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी और पुराने कचरे के त्वरित निस्तारण हेतु लक्ष्य तय करके कार्यवाही करने के निर्देश दिये। बैठक में समिति के सदस्य लोकेंद्र सिंह बिष्ट,सीडीओ जय भारत सिंह वीसी से एवं एडीएम मुक्ता मिश्र, डीपीआरओ प्रताप पंवार, स्वजल से प्रताप मटूड़ा उपस्थित रहे तथा समस्त बीडीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े।

छात्रों के 'दर्द' पर सियासत का 'पहरा'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। दिल्ली में लाठियां चलीं। जंतर-मंतर से संसद मार्ग तक तनाव की तस्वीरें आईं। उसके बाद राजनीति ने वही किया, जो वह अक्सर करती है घटना को मुद्दे में बदला और मुद्दे को चुनाव में। दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लोकतंत्र का दमनकारी चेहरा बताया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास की ओर किए गए विरोध मार्च को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए पलटवार शुरू कर दिया। इसका असर केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच करने निकले। उधर कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने दफ्तर के बाहर डट गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बैरिकेडिंग कर दी। नारे गूंजे, आरोप लगे, जवाबी आरोप लगे, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह था कि आखिर यह लड़ाई किसके लिए थी छात्रों के लिए, लोकतंत्र के लिए या 2027 और 2029 की राजनीति के लिए?

राजनीति की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह हर घटना का अपना अर्थ गढ़ लेती है। छात्र आंदोलन हो तो सत्ता उसे कानून-व्यवस्था का मामला बताती है। विपक्ष उसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कहता है। जनता दोनों पक्षों को सुनती है और फिर अपने जीवन की ओर लौट जाती है, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की समस्याएं न नारों से हल होती हैं और न प्रेस कान्फ्रेंस से। देहरादून में भाजपा का कांग्रेस मुख्यालय की ओर कूच केवल विरोध कार्यक्रम नहीं था। यह अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने का भी कार्यक्रम था कि पार्टी राहुल गांधी की राजनीति का जवाब सड़क पर भी देगी। कांग्रेस ने भी पीछे हटने का संकेत नहीं दिया।

◆दिल्ली में लाठियां, देहरादून में हंगामी जंग, सवाल वही, लड़ाई युवाओं की या चुनाव की
◆जंतर-मंतर से संसद मार्ग और देहरादून की सड़कों तक छिड़ा राजनीतिक घमासान
◆सवालों के घेरे में घिरी लाठीतंत्र की तस्वीरें और 2027-2029 की चुनावी गोटियां

कार्यकर्ताओं को मुख्यालय पर जुटाया गया। पुलिस को पहले से अंदेशा था कि दोनों पक्ष आमने-सामने आए तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए बैरिकेडिंग पहले लगी, समझाइश बाद में हुई।

उत्तराखंड की राजनीति में यह दृश्य नया नहीं है, लेकिन इसका समय बेहद महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, फिर भी राजनीतिक दल सड़क पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगे हैं। भाजपा जानती है कि यदि छात्र आंदोलनों और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष को खुला मैदान मिल गया तो उसका राजनीतिक असर चुनाव तक जा सकता है। कांग्रेस समझती है कि दिल्ली की हर घटना को उत्तराखंड के युवाओं से जोड़कर सरकार को घेरा जा सकता है। यानी लड़ाई केवल दिल्ली की नहीं है। लड़ाई उस राजनीतिक नैरेटिव की है, जो आने वाले चुनावों में जनता के मन में बैठेगा।

दिलचस्प यह भी है कि दोनों दल लोकतंत्र की रक्षा का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि छात्रों पर लाठी चलाना लोकतंत्र की हत्या है। भाजपा कहती है कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। दोनों के अपने-अपने तर्क हैं। लेकिन आम नागरिक पूछ रहा हैकृक्या लोकतंत्र केवल तब खतरे में पड़ता है जब विरोधी दल सड़क पर उतरता है? युवाओं की नजर से देखें तो तस्वीर और अलग दिखाई देती है। उन्हें रोजगार चाहिए, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में भरोसा चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं में अक्सर मुद्दों से अधिक मुद्दों की राजनीति दिखाई देती है। यही कारण है कि कई बार सड़क पर छात्रों की आवाज पीछे छूट जाती है और राजनीतिक दलों के झंडे आगे निकल जाते हैं।

देहरादून में पुलिस ने दोनों दलों को आमने-सामने आने से रोक दिया। कानून-व्यवस्था के लिहाज से यह जरूरी भी था। लेकिन यह दृश्य एक बड़ा राजनीतिक संकेत छोड़ गया। उत्तराखंड अब केवल पहाड़, पर्यटन और चारधाम की राजनीति

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'सपने' नीलाम और नीतियां 'नाकाम'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। भारतीय राजनीति में कई बार ऐसे क्षण आते हैं, जब कोई एक मुद्दा अचानक चुनावी गणित से बड़ा दिखाई देने लगता है। बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली, भर्ती, शिक्षा और युवाओं का भविष्य यह विषय लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। हाल के छात्र आंदोलनों के बाद इन मुद्दों पर राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है। कांग्रेस ने इन आंदोलनों के साथ खुलकर अपनी एकजुटता दिखाई है, जबकि भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से देश की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है।

भाजपा का तर्क साफ है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी हर आंदोलन को राजनीतिक मंच में बदलना चाहते हैं। उसके अनुसार, छात्रों की चिंताओं का समाधान संवाद और संस्थागत प्रक्रिया से होना चाहिए, न कि सड़क की राजनीति से। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष युवाओं के असंतोष को सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति भी कम स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी लगातार छात्रों, युवाओं और भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यदि युवाओं की आवाज दबाई जाएगी, तो विपक्ष उनके साथ खड़ा होगा। पार्टी इसे केवल छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि भविष्य, अवसर और जवाबदेही का सवाल बता रही है। यहीं राजनीति दिलचस्प हो जाती है।

कई वर्षों तक राष्ट्रीय राजनीति की धुरी मंदिर, राष्ट्रवाद, सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं और नेतृत्व की छवि के इर्द-गिर्द घूमती रही। लेकिन यदि युवाओं की रोजमर्रा की चिंताएं रोजगार, परीक्षाएं, शिक्षा और

◆पेपर लीक-बेरोजगारी के खिलाफ सुलगी देशभर में चिंगारी
◆सत्ता की खामोशी, विपक्ष का दांव, लटका युवाओं का कल
◆भाजपा का आरोप राहुल छात्रों के कंधों पर कर रहे राजनीति
◆कांग्रेस पार्टी का जवाब युवाओं की लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे

अवसर चुनावी विमर्श के केंद्र में आती हैं, तो राजनीतिक दलों की रणनीतियों पर भी असर पड़ सकता है। क्या इससे राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल बदल रहा है? इसका अंतिम उत्तर अभी देना जल्दबाजी होगी। भारत का चुनावी व्यवहार कई कारकों से प्रभावित होता है स्थानीय मुद्दे, नेतृत्व, गठबंधन, सामाजिक समीकरण और आर्थिक परिस्थितियां, सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि छात्र आंदोलनों ने युवाओं से जुड़े प्रश्नों को राष्ट्रीय बहस में अधिक प्रमुखता से ला दिया है।

भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देना नहीं है, बल्कि यह भी दिखाना है कि वह युवाओं की चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी चुनौती कम नहीं है। यदि वह छात्रों के मुद्दों को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाती है, तो उसे केवल विरोध तक सीमित रहने के बजाय ठोस नीतिगत विकल्प भी प्रस्तुत करने होंगे। राहुल गांधी की सार्वजनिक मौजूदगी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा जरूर पैदा की है। वहीं भाजपा अपने संगठन और सरकार की उपलब्धियों के आधार पर इस नैरेटिव का मुकाबला करने में जुटी है। दोनों दल यह समझते हैं कि भारत की बड़ी युवा आबादी चुनावी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या छात्र आंदोलन केवल विरोध का प्रतीक रहेगा, या वह शिक्षा, रोजगार और परीक्षा सुधार जैसे मुद्दों पर स्थायी राजनीतिक बहस को जन्म देगा?

लोकतंत्र में किसी भी आंदोलन का महत्व केवल उसके नारों से नहीं, बल्कि उससे निकले नीति-परिवर्तनों से तय होता है। यदि इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम बेहतर परीक्षा व्यवस्था, अधिक पारदर्शिता, युवाओं के लिए अवसर और जवाबदेही के रूप में सामने आता है, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता होगी। यदि यह केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित रह गया, तो सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों का होगा जिनके सवाल इस बहस की शुरुआत का कारण बने।

राजनीति का नया मोड़ शायद यही है युवा अब केवल वोटर नहीं, बल्कि राजनीतिक विमर्श का सक्रिय केंद्र बनते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि कौन-सा दल उनकी आकांक्षाओं को विश्वसनीय ढंग से संबोधित कर पाता है और कौन केवल राजनीतिक संदेश देने तक सीमित रह जाता है।

धौलछीना में तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर संपन्न, 182 लोगों ने उठाया विशेषज्ञ सेवाओं का लाभ

अल्मोड़ा(आरएनएस)। भैंसियाछाना ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धौलछीना में आयोजित तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. हरीश चंद्र पंत के निर्देशन और नोडल अधिकारी डॉ. दीपक शर्मा के नेतृत्व में आयोजित शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना रहा। शिविर में जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा से पहुंचे हड्डी रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ईएनटी, नेत्र रोग और बाल रोग विशेषज्ञों के साथ आयुष विभाग की टीम ने मरीजों की जांच कर नि:शुल्क परामर्श दिया। शिविर के दौरान चेस्ट एक्स-रे, टीबी स्क्रीनिंग, गैर संचारी रोग (एनसीडी) की जांच, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत परीक्षण एवं परामर्श, ई-रक्तकोष से संबंधित सेवाएं तथा पात्र लाभार्थियों के दिव्यांग प्रमाण-पत्र भी बनाए गए। तीन दिवसीय शिविर में कुल 182 मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इनमें 41 हड्डी रोग, नौ ईएनटी, 11 स्त्री एवं प्रसूति रोग, 49 नेत्र रोग, 32 बाल रोग तथा 4० आयुष चिकित्सा से संबंधित मरीज शामिल रहे। शिविर के दौरान 115 लोगों के चेस्ट एक्स-रे भी किए गए। शिविर में डॉ. प्रमोद मेहता (अस्थि रोग), डॉ. आंचल (स्त्री एवं प्रसूति रोग), डॉ. मोनिका (ईएनटी) और डॉ. वी.एल. जायसवाल (बाल रोग) सहित जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ टीम ने सेवाएं दीं। कार्यक्रम के संचालन में प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. संजीव शुक्ला, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक दीपक पंत, डॉ. संदीप, डॉ. अदिति तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य चिकित्सकों, कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और सहयोगी स्टाफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

किच्छा में 1.37 करोड़ की 6 विकास योजनाएं स्वीकृत: बेहड़

रुद्रपुर(आरएनएस)। विधायक तिलकराज बेहड़ ने बताया कि उनके प्रयासों से राज्य योजना, जिला योजना एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत 1.37 करोड़ रुपये की छह महत्वपूर्ण विकास योजनाओं को स्वीकृति मिली है। जारी बयान में विधायक बेहड़ ने बताया कि राज्य योजना के तहत 71 लाख की लागत से महाराजपुर-कनकपुर 2.०5० किलोमीटर प्रीमिक्स कारपेट मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जिला योजना के तहत लालपुर में 13 लाख से 18० मीटर सड़क, 12 लाख से 15० मीटर सड़क, 7 लाख से लालपुर-खमरिया रोड से 1०० मीटर सड़क और 14 लाख से लालपुर वार्ड-2 में 2०० मीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सैजना में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र योजना के तहत 2० लाख की लागत से कब्रिस्तान में टिन शेड, फर्श एवं इंडिया मार्का हैंडपंप का निर्माण कराया जाएगा। बेहड़ ने बताया कि कनकपुर काली मंदिर से गौरीकलां तक 2.5 किलोमीटर सड़क के डामरीकरण तथा रुद्रपुर प्रथम स्थित ज्येष्ठा कॉलोनी की 5०० मीटर सड़क के डामरीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। इन दोनों सड़कों की स्वीकृति भी शीघ्र मिलने की उम्मीद है।

कंपनी में श्रमिकों का हंगामा, एचआर हेड को हटाने की मांग

रुद्रपुर(आरएनएस)। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर मीक फार्मा कंपनी के श्रमिकों ने कार्य बहिष्कार कर फैक्ट्री गेट पर हंगामा किया। महिला श्रमिकों ने कंपनी के एचआर हेड पर अभद्रता और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। प्लांट हेड ने श्रमिकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। इसके बाद श्रमिक शांत हुए। लालपुर स्थित मीक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि वे पिछले 15 वर्षों से कंपनी में कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें मात्र आठ हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। आरोप लगाया कि अतिरिक्त समय तक काम कराने के बावजूद ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाता और उन्हें अपने पीएफ संबंधी जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। महिला श्रमिकों ने आरोप लगाया कि एचआर हेड उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। उनसे समय से पहले पंचिंग करवाई जाती है और मोबाइल फोन अपने पास नहीं रखने दिया जाता है, जिससे पारिवारिक आपात स्थिति में भी उन्हें सूचना नहीं मिल पाती। उन्होंने एचआर हेड पर श्रमिकों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने और वेतन वृद्धि की मांग की। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के कारण फैक्ट्री में अफरातफरी का माहौल बना रहा। हंगामा बढ़ने पर प्लांट हेड अशोक शर्मा फैक्ट्री गेट पर पहुंचे और श्रमिकों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद श्रमिक फैक्ट्री के अंदर चले गए। अशोक शर्मा ने बताया कि श्रमिकों की समस्याओं से फैक्ट्री प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन करने वालों में चित्रा देवी, शीला देवी, रूपवती दिवाकर, निशा पालीवाल, आशा गौतम, सीमा, अंजली, पूजा, संगीता, सोनू, मुनीश, शिवम, हर्ष, अंकित और समीर आदि शामिल रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

सत्ता की 'होड़' और अन्य दलों का 'खेल'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2०27 में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी रणभूमि में अपनी-अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सत्ता विरोधी माहौल को अपने पक्ष में करने की रणनीति पर काम कर रही है। दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए लगातार सक्रियता बढ़ा रहे हैं। इस बार चुनावी मुकाबला केवल भाजपा और कांग्रेस तक सीमित नहीं रहेगा। भले ही सत्ता की सीधी लड़ाई इन्हीं दो दलों के बीच मानी जा रही हो, लेकिन छोटे दल कई सीटों पर मुकाबले को त्रिकोणीय या बहुकोणीय बनाकर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश नेतृत्व लगातार संगठनात्मक बैठकों, कार्यकर्ता सम्मेलनों और जनसंपर्क अभियानों में व्यस्त हैं। भाजपा की रणनीति साफ हैकृसरकार की योजनाओं, चारधाम परियोजनाओं, सड़क, रेल, पर्यटन, निवेश और महिला कल्याण कार्यक्रमों को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाना। पार्टी गांव-गांव और घर-घर पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। बूथ समितियों को सक्रिय करने के साथ-साथ युवा, महिला और सोशल मीडिया नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। भाजपा का मानना है कि मजबूत संगठन और लाभार्थी वर्ग उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं।

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, किसानों और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है। प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन, संवाद कार्यक्रम और जनसभाओं के जरिए सरकार की नीतियों को जनता के सामने चुनौती देने की कोशिश कर रही है। पार्टी का प्रयास है कि सत्ता विरोधी भावना को एक संगठित राजनीतिक अभियान में बदला जाए। हालांकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठनात्मक एकजुटता और स्थानीय स्तर पर नेतृत्व के बीच तालमेल बनाए रखना भी है।

बहुजन समाज पार्टी भी प्रदेश में अपने संगठन को दोबारा सक्रिय करने में जुट गई है। पार्टी दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बसपा की रणनीति उन विधानसभा क्षेत्रों पर केंद्रित है जहां उसका परंपरागत वोट प्रतिशत चुनावी समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। पार्टी छोटे-छोटे कार्यकर्ता सम्मेलनों और सदस्यता अभियानों के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी भी सीमित संगठन होने के बावजूद उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। विशेषकर तराई और सीमावर्ती क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। सपा का लक्ष्य फिलहाल बड़े पैमाने पर सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक मौजूदगी और वोट आधार को मजबूत करना माना जा रहा है।

- भाजपा-कांग्रेस ही नहीं, बसपा, सपा और आप भी उतरी मैदान में
- संगठन विस्तार, कार्यकर्ता सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान तेज
- 2027 की सत्ता की जंग का बिगुल उत्तराखंड में समय से पहले बजा

दिल्ली और पंजाब की राजनीति के बाद उत्तराखंड में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता पूरी तरह समाप्त नहीं की है। पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और रोजगार जैसे मुद्दों पर फिर से जनता के बीच जाने की तैयारी में है। हालांकि पिछले चुनाव के बाद संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन पार्टी नए चेहरों और स्थानीय नेतृत्व के सहारे अपनी पहचान फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल सहित अन्य क्षेत्रीय दल भी राज्य की अस्मिता, मूल निवास, भू-कानून, रोजगार, जल-जंगल-जमीन और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। हालांकि पिछले चुनावों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सीमित रहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि स्थानीय मुद्दे चुनाव के केंद्र में आए तो कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव बढ़ सकता है।

इस बार लगभग सभी दलों की रणनीति में दो वर्ग सबसे महत्वपूर्ण दिखाई दे रहे हैं युवा और महिलाएं। युवाओं के लिए रोजगार, भर्ती, शिक्षा और स्वरोजगार प्रमुख मुद्दे हैं, जबकि महिलाओं के लिए महंगाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वयं सहायता समूह और कल्याणकारी योजनाएं चुनावी एजेंडे का हिस्सा बन रही हैं। राजनीतिक दलों का मानना है कि यही दो वर्ग चुनाव परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

उत्तराखंड की राजनीति में क्षेत्रीय संतुलन हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। गढ़वाल और कुमाऊं के साथ-साथ पहाड़ और मैदान के मुद्दों का संतुलन साधना हर दल की मजबूरी है। पलायन, खाली होते गांव, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे मुद्दे पर्वतीय क्षेत्रों में चुनावी बहस का केंद्र बन सकते हैं, जबकि तराई क्षेत्रों में कृषि, उद्योग और रोजगार प्रमुख विषय रहेंगे। राजनीतिक दलों की लगातार बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत हैं कि 2०27 का चुनाव अब केवल कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि राजनीतिक तैयारी का वर्तमान बन चुका है। बैठकों, रैलियों, सदस्यता अभियानों, जनसंवाद कार्यक्रमों और सोशल मीडिया अभियानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद समय से पहले हो चुका है।

उत्तराखंड की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अब केवल चुनावी घोषणाओं से नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों की समझ और जनता के बीच लगातार मौजूदगी से तय होगा। भाजपा अपनी सरकार के कामकाज पर भरोसा जता रही है, कांग्रेस बदलाव की उम्मीद जगाने में लगी है, जबकि बसपा, सपा, आप और क्षेत्रीय दल इस मुकाबले में अपनी प्रासंगिकता साबित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आने वाले महीनों में यह सक्रियता और तेज होने की संभावना है, क्योंकि 2027 की लड़ाई का पहला दौर अब मैदान में उतर चुका है।

सीलिंग और नजूल भूमि पर बसे परिवारों को दिए जाएं बिजली कनेक्शन

रुद्रपुर (आरएनएस)। सीलिंग, नजूल और ट्रांजिट कैंप की दानपत्र भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे।

प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने डीएम नितिन सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपकर तत्कालीन जिलाधिकारी के 31 मई, 2023 और सचिव, विकास प्राधिकरण के 28 नवंबर, 2025 के आदेशों को निरस्त करते हुए जिला मुख्यालय की सभी आवासीय कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की।

पूर्व विधायक ठुकराल ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच कई परिवार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। बिजली कनेक्शन नहीं मिलने से सैकड़ों परिवारों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित को देखते हुए पूर्व में जारी आदेशों को निरस्त कर लोगों को राहत प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के विभिन्न वार्डों और आसपास की मलिन बस्तियों में हजारों परिवार वर्षों से दानपत्र भूमि पर निवास कर रहे हैं। स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और रजिस्ट्री नहीं होने के कारण उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है।

वहीं फाजलपुर मेहरोला क्षेत्र की प्रीत विहार, तराई विहार, लोक विहार, बराड़ नगर और अपना इन्क्लेव समेत अन्य कॉलोनियों में भी सैकड़ों परिवार स्थायी रूप से रह रहे हैं। इनमें कई लोग रजिस्ट्रीयुक्त तथा नजूल भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन भूमि सीलिंग संबंधी प्रतिबंधों के चलते न तो संपत्ति का क्रय-विक्रय हो पा रहा है और न ही दाखिल-खारिज व रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो पा रही है। इसका सीधा असर बिजली कनेक्शन प्राप्त करने पर पड़ रहा है।

ज्ञापन में मांग की गई कि सीलिंग, नजूल और दानपत्र भूमि पर बसे परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखा जाए। साथ ही इन परिवारों को मालिकाना हक प्रदान कर संबंधित भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने की भी मांग उठाई गई। इस दौरान संजीव गुप्ता, संजय ठुकराल, ब्रजेन मंडल, ललित बिष्ट, रामकुमार गुप्ता, संजय कुमार, कुंवर पाल कोली, हिम्मत राम कोली, उनैजा फातमा, विमला देवी, सुनीता, ममता, कलावती, आशिया अंसारी, नाजमा, नेहा, रूबीना, शमीला, मेहनाज बी, विवेक, अंजुम, राहुल, यासमीन, काव्या, बाबूराम, फैसल, रूबल कौर, दीपक, रेशमा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

बच्चों के दांतों की सफाई करते समय न करें ये गलतियां, हो सकता है नुकसान

बच्चों की दांतों की सफाई करना एक जरूरी काम है, लेकिन कई बार माता-पिता कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे बच्चों के दांतों को नुकसान पहुंच सकता है। इन गलतियों में टूथब्रश का गलत चयन, ब्रश करने का तरीका, फ्लोराइड का अधिक उपयोग और बच्चों को खुद ब्रश करने देना शामिल है। आइए आज हम आपको इन गलतियों के बारे में विस्तार से बताते हैं ताकि आप इनसे बच सकें और आपके बच्चों के दांत स्वस्थ रहें।

सही टूथब्रश का चयन न करना

बच्चों के लिए सही टूथब्रश का चयन करना बहुत जरूरी है। अक्सर माता-पिता बड़े आकार के ब्रश का उपयोग करते हैं, जो बच्चों के छोटे मुंह के लिए सही नहीं होता। इसके बजाय छोटे सिर वाले मुलायम बालों वाले ब्रश का चयन करें ताकि वे आसानी से हर कोने तक पहुंच सकें और बच्चों के दांतों को अच्छे से साफ कर सकें। इसके अलावा टूथब्रश की नोक को भी ध्यान में रखें।

टूथब्रश करने का तरीका

बच्चों को टूथब्रश करने का तरीका सिखाते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार माता-पिता जल्दी-जल्दी में बच्चों का ब्रश करा देते हैं या उन्हें खुद ब्रश करने देते हैं, जिससे वे सही तरीके से सफाई नहीं कर पाते। बच्चों को धीरे-धीरे और सही तरीके से ब्रश कराना चाहिए ताकि वे हर हिस्से तक पहुंच सकें और उनके सभी दांत साफ रहें। इसके अलावा बच्चों को ब्रश करते समय गुनगुनाने या कहानी सुनाने से भी मजा आता है।

फ्लोराइड का अधिक उपयोग

फ्लोराइड दांतों की सुरक्षा के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसका अधिक उपयोग बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। अधिक फ्लोराइड से बच्चों को फ्लोराइड से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे दांतों में पीलापन आ सकता है या वे कमजोर हो सकते हैं। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह अनुसार ही फ्लोराइड का उपयोग करें और बच्चों को थोड़ी मात्रा में ही फ्लोराइड युक्त पेस्ट दें। इसके अलावा बच्चों को पानी से कुल्ला करने की आदत भी सिखाएं।

बिना निगले पानी से कुल्ला करना

बच्चों को ब्रश करने के बाद पानी से कुल्ला करना सिखाना बहुत जरूरी है ताकि उनका मुंह साफ रहे और बैक्टीरिया दूर रहें। हालांकि, कई बार माता-पिता यह गलती कर देते हैं कि वे बच्चों को पानी निगलवा देते हैं, जिससे उनके पेट पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा बच्चों को पानी निगलवाने से पहले उनका मुंह अच्छी तरह साफ कर लें और फिर उन्हें पानी पीने दें।

खुद ब्रश करने देना

बच्चों को खुद ब्रश करने देना अच्छा होता है, लेकिन अगर वे छोटे हों तो उन्हें खुद से ब्रश करने देना गलत हो सकता है। छोटे बच्चे सही तरीके से ब्रश नहीं कर पाते, जिससे उनके दांतों पर गंदगी रह जाती है। बेहतर होगा कि आप पहले खुद ब्रश करें और फिर उन्हें सिखाएं कि कैसे हर हिस्से तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद उन्हें खुद ब्रश करने दें ताकि वे सही तरीके से सफाई कर सकें।

गर्मियों के दौरान बनाकर खाएं संतरे की कैंडी आइसक्रीम, जानिए रेसिपी

गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की मौसमी बीमारियों के साथ आता है, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा परेशानी पैदा करती हैं। हालांकि, अगर इस दौरान संतरे का सेवन किया जाए तो इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और शरीर ठंडा रहता है। आइए आज हम आपको संतरे की कैंडी आइसक्रीम बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

इस आइसक्रीम को बनाने के लिए जरूरी सामग्रियां

एक कप संतरे का रस, एक चौथाई कप चीनी का पाउडर, एक चौथाई कप पानी, आधा कप दूध, एक चौथाई कप मलाई, एक चौथाई छोटी चम्मच इलायची का पाउडर, एक छोटी चम्मच नींबू का रस, कुछ संतरे के टुकड़े, दो बड़ी चम्मच काजू और किशमिश। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपने परिवार के अनुसार सामग्रियों की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं।

इस तरह से करें आइसक्रीम बनाने की शुरूआत

सबसे पहले एक पैन में पानी और चीनी का मिश्रण बनाकर उसे एक मिनट तक पकाएं, फिर इसमें संतरे का रस डालें और मिश्रण को 5 से 10 मिनट तक उबालें। इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक दूसरे बर्तन में दूध, मलाई, इलायची का पाउडर, नींबू का रस और संतरे के टुकड़े मिलाकर उन्हें अच्छी तरह से फेंट लें, फिर इसमें पहले वाला ठंडा मिश्रण मिलाएं।

ऐसे आइसक्रीम को जमाने के लिए करें तैयार

अब आइसक्रीम के मिश्रण को किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रीजर में जमाने के लिए रख दें। जब आइसक्रीम जमकर तैयार हो जाए तो इसे सर्विंग कप में डालकर इसके ऊपर काजू और किशमिश डालकर इसे परोसें। आप चाहें तो इस आइसक्रीम को बच्चों के जन्मदिन पर भी बना सकते हैं।

आइसक्रीम को बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

1) आइसक्रीम को जमाने के लिए ज्यादा समय न दें क्योंकि इससे इसका स्वाद बिगड़ सकता है। 2) इस आइसक्रीम को जमाने के लिए क्रीम का इस्तेमाल न करें। 3) आप चाहें तो काजू और किशमिश की जगह बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4) इलायची के पाउडर को आइसक्रीम के मिश्रण में तब डालें, जब यह ठंडा हो जाए।

प्रदूषण से बढ़ गया है बालों का झड़ना ?

पर्यावरणीय कारक भी बालों के झडने़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं क्योंकि प्रदूषण से बालों में रूखापन, बालों की जड़ों का कमजोर होना और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बालों को जहरीली हवा के दुष्प्रभाव से बचाना महत्वपूर्ण हो गया है। आइए आज आपको कुछ ऐसी टिप्स देते हैं, जो बालों को पोषण देने और विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद कर सकते हैं।

घर से बाहर निकलने से बचें

बालों को प्रदूषण और अन्य विषाक्त पदार्थों से बचाने का सबसे आसान तरीका है कि आप घर से बाहर निकलने से बचें।हालांकि, अगर आपका घर से निकलना बहुत जरूरी है तो पहले अपने सिर को किसी चीज से ढकें। इसके लिए आप हेयर स्कार्फ से लेकर बंडाना और टोपी आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं।यह न सिर्फ एक शील्ड की तरह काम करेगें, बल्कि आपको स्टाइलिश लुक भी देगें।

सल्फेट मुक्त शैंपू और कंडीशनर का करें इस्तेमाल

बालों को झडने़ से रोकने के लिए सल्फेट मुक्त शैंपू का इस्तेमाल करना लाभदायक है। यह बालों को मॉइस्चराइज करने और पोषण देने में प्रभावी माना जाता है।आप चाहें तो शिकाकाई, मोरिंगा और प्याज के तेल से बने शैंपू को भी चुन सकते हैं।इसके अतिरिक्त फ्रिज और दोमुंहे बालों से बचाव के लिए शैंपू के बाद एक हाइड्रेटिंग कंडीशनर का भी इस्तेमाल जरूर करें।

हेयर मास्क का इस्तेमाल है जरूरी

बालों की समस्या से बचाव के लिए हफ्ते में 1 बार बालों को पोषण देने वाले हेयर मास्क का इस्तेमाल जरूरी है।हेयर मास्क आपके बालों को मजबूत भी करेगा और उनके टूटने के साथ रूखेपन को भी रोकेगा।इसके लिए केला, एवोकाडो का गूदा, पुदीना और शहद को मिलाएं और फिर इस मिश्रण को अपने बालों में लगाएं। करीब 30-45 मिनट बाद बालों को पानी से धो लें।इसके एक बार इस्तेमाल से ही आपको असर नजर आने लगेगा।

बालों में तेल लगाएं

बालों को प्रदूषण से बचाने के साथ-साथ बालों को मजबूत और मॉइस्चराइज करने के लिए हफ्ते में 2 बार बालों में तेल जरूर लगाएं।बालों में तेल की मालिश करने से स्कैल्प में नमी बरकरार रहती है। इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। घने बालों के लिए नारियल के तेल में गुड़हल के फूलों का पेस्ट लगाकर इस्तेमाल करें। बालों को स्वस्थ और खूबसूरत बनाने के लिए गुड़हल का इस्तेमाल इन तरीकों से भी करें।

डाइट और हाइड्रेशन पर दें ध्यान

जब भी बात बालों की देखभाल की आती है तो डाइट अहम भूमिका निभाती है।ऐसे में अपनी डाइट में आयरन, जिंक, बायोटिन, नियासिन, विटामिन सी और डी और ओमेगा-6 जैसे पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में शामिल करें।इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी बालों के टूटने का कारण बन सकता है और सर्दियों में यह समस्या गंभीर हो जाती है।इस कारण पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और पानी की मात्रा से भरपूर फल और सब्जियों का अधिक सेवन करें।

शब्द सामर्थ्य -097

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. ठुड्डी पर के बाल, ठुड्डी, ठोढ़ी 3. विशेष और सामान्य (आदमी), आम और खास लोग (उ.) 5. इच्छा, हसरत, अभिलाषा 6. शारीरिक कोमलता, सुकुमारता (उ.) 7. सविनय, विनती पूर्वक 10. बिलख-बिलख कर रोना 11. कहानी, उपन्यास 12. कुशल, दक्ष, विशेषज्ञ 13. भार, दबाव 14. शुभ-अशुभ की पूर्व सूचना, शुभ अवसर पर होने वाला मंगल कार्य संबंधी गीत 15. एहसान, भलाई, हित 17. सूत काटने, लपेटने में काम आने वाली चर्खे से लगी सलाई 19. एक हिन्दी महीना, श्रावण 20. सप्ताह का एक दिन, बृहस्पतिवार।

ऊपर से नीचे

1. जंगल में लगी आग, दावाग्नि 2. मूल्य, दाम 4. स्वतंत्र, स्वाधीन 5. संकट, कष्ट, दर्द 7. लकड़ी, कन्या, कानों में पहनने का छल्ला, श्रेष्ठ 8. बेइज्जती, अनादार 9. शोभा, सुंदरता, बसंत ऋतु 10. तबाह करने वाला,विनाशक 11. इस समय 13. असुर, राक्षस, दैत्य 14 ए. गुरुमंत्र, बहुत अच्छी युक्ति 15. पर्व, त्यौहार 16. शिकायत, उलाहना, ग्लानि 17. वृक्ष, पेड़ 18. मुंह से निकलने वाला थूक जैसा पदार्थ।

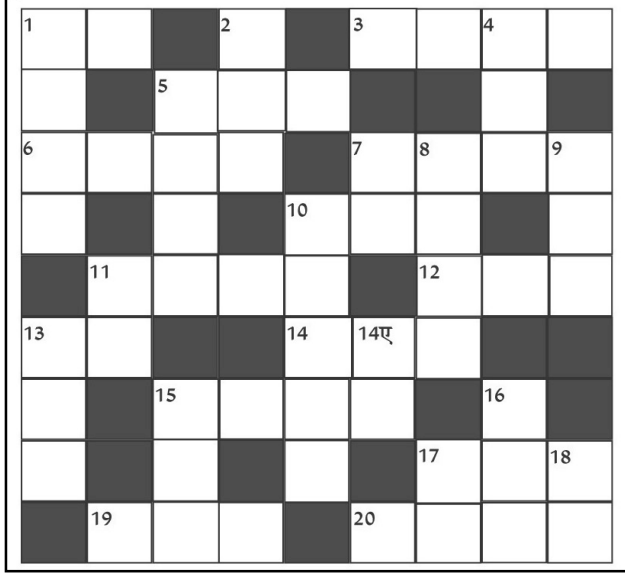

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 96 का हल

खा	म	खां			इं			
स	ह		ब	र	सा	त		प
	क	हा	नी		न	क	च	ढ़ा
त			स्ब			ली		ई
क	या	म	त		क	फ	न	
दी		र्दा		बा	बू		ह	वा
र	ह	ना		ल	त	खो	र	
	वा		नौ	क	र			सा
भा	ई		का			बा	द	ल

घर के अंदर शुद्ध हवा के लिए अपनाएं ये तरीके

देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में जा रहा है।ऐसे में घर के अंदर भी सांस देने में दिक्कत हो रही है। इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।इससे बचने के लिए घर में हवा को शुद्ध करना जरूरी है।आइये आज 5 ऐसे तरीके जानते हैं, जिनसे घर के अंदर की वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है।

इनडोर पौधे करेंगे मदद

पौधे घर के वातावरण को तरोताजा रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे घर के अंदर की हवा शुद्ध रहती है, जिससे आपको बेहतर सांस लेने में मदद मिलती है।वैज्ञानिक रूप से पौधे हवा से फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और ट्राइक्लोरोइथेन जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों को हटाने में मदद करते हैं, जिससे आसपास की हवा ताजा रहती है।इसके लिए इंग्लिश आइवी, फिकस, बैंबू पाम, स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे अच्छे इनडोर पौधे लगाएं।

वेंटिलेशन है जरूरी

घर के अंदर सही वेंटिलेशन होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हवा को इधर-उधर जाने का रास्ता मिलता है।इस प्रक्रिया के साथ घर के अंदर का प्रदूषण भी दूर हो जाता है और आपको ताजी हवा मिलती है।इसके लिए आप रसोई और वॉशरूम जैसी जगहों के पास एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल कर सकते हैं।इससे हवा घूमती रहती है और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होता है।

भाप लें

शुद्ध वायु के लिए कुछ प्राकृतिक और घरेलू उपचार सदियों से होते आ रहे हैं, जो प्रभावी भी हैं। इन्हीं उपायों में भाप लेना भी शामिल है।भाप लेने से फेफड़ों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और श्वसन पथ को भी साफ किया जा सकता है। साथ ही यह वायुमार्ग को भी आराम पहुंचाता है।अतिरिक्त लाभ के लिए आप स्टीम कंटेनर में नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें भी मिलाकर भाप ले सकते हैं।

एयर प्यूरीफायर

घर की हवा में मौजूद धूल को दूर करने के लिए आप एक एयर प्?यूरीफायर भी खरीद सकते हैं। इसे घर के बीचों-बीच रखें। इससे आपके घर की हवा काफी साफ होने लगेगी।हालांकि अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं तो अच्छे फिल्टर वाला खरीदें ताकि यह हानिकारक वायु कणों को अच्छे से हटा सके।एयर प्यूरिफायर धुआं, पालतू जानवर की रूसी और अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य प्रदूषण को खत्म कर सकता है।

गुलाब की पंखुड़ियों को खाने के हैं अनोखे फायदे!

गुलाब का फूल महज सजावट की वस्तु नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल अन्य कई चीजों में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए महिलाएं अपने स्किन केयर में गुलाब के फूलों से बनी चीजों को जरूर शामिल करती हैं। गुलाब जल के बिना शायद ही महिलाओं का कोई स्किन केयर पूरा होता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं गुलाब के फूल की पंखुडियां खाना भी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। जी हां, गुलाब के फूलों का सेवन करके आप त्वचा पर गुलाब जैसा ही सॉफ्ट और गुलाबी निखार ला सकती हैं।

दरअसल गुलाब के फूल दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं, त्वचा पर इसके फायदे भी उतने ही लाजवाब होते हैं। इसीलिए कई महिलाएं गुलाब के फूलों का रोज वॉटर, रोज ऑयल और रोज पाउडर का फेस पैक बनाकर इसे चेहरे पर अप्लाई करती हैं। मगर, क्या आप गुलाब के फूलों को खाने के फायदों से वाकिफ हैं। अगर नहीं, तो आइए हम आपको बताते हैं गुलाब के फूलों को खाने के कुछ अनोखे फायदों के बारे में।

त्वचा की परेशानियां होंगी दूर : नियमित रूप से गुलाब के फूलों का सेवन करने के त्वचा से जुड़े भी कई फायदे हैं। इसकी मदद से आप स्किन की डलनेस और ड्रायनेस जैसी दिक्कतों से चुटकियों में निजात पा सकते हैं।

निखरी त्वचा का राज : गुलाब के फूलों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व त्वचा के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने के साथ-साथ स्किन इंफैक्शन से भी दूर रखने का काम करता है। जिससे आपकी त्वचा सुंदर और हेल्दी बनी रहती है।

विटामिन्स से भरपूर : गुलाब के फूलों में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में गुलाब की पत्तियों का सेवन करने से त्वचा के दाग-धब्बे, सीजनल इंफैक्शन और एलर्जी से दूर रहने में मदद मिलती है।

गुलकंद का करें इस्तेमाल :अगर आपको गुलाब की पत्तियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर, आप अपनी त्वचा को गुलाब सा निखार देने की चाहत रखते हैं, तो ऐसे में आप गुलकंद का स्वाद चख सकती सकते हैं। बता दें कि गुलकंद को गुलाब की पत्तियों, शहद और शक्कर मिक्स करके बनाया जाता है, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है।

गुलाब के फूलों से बनाएं चाय :अगर आप चाय के बेहद शौकीन हैं, तो गुलाब के फूलों की चाय भी ट्राय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए 1 कप गर्म पानी में गुलाब के फूलों की पंखुडियां मिलाकर 5 मिनट तक उबालें। अब इस पानी को 2-3 मिनट तक ढक कर रख दें। इसके बाद पानी को छान लें और शहद या चीनी के साथ गुलाब की चाय का सेवन करें।

इंडियन हो या वेस्टर्न, हर लुक में बला की खूबसूरत लगती हैं एक्ट्रेस सरगुन मेहता

सरगुन मेहता इन दिनों फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी ये कॉमेडी फिल्म पिछले माह को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों से बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और उम्मीद है कि ये बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग करने वाली है। सरगुन मेहता फिल्मों के साथ-साथ अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज को लेकर भी लगातार चर्चा में रहती हैं।

पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइजी कैरी ऑन जट्टा 4 में सरगुन मेहता लीड रोल में हैं। वो फिल्म में प्रीत नाम की लड़की का रोल निभा रही हैं। इसमें उनकी जोड़ी गिप्पी ग्रेवाल के साथ बनी है। दोनों की केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। सरगुन मेहता ने कैरी ऑन जट्टा फ्रैंचाइजी में पहली बार एंट्री की है। इससे पहले इस फ्रैंचाइजी की फिल्मों में सोनम बाजवा और माहिरा शर्मा जैसी हसीनाएं नजर आई थीं। फिल्म में सरगुन की एक्टिंग दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। फिल्मों में दमदार एक्टिंग के साथ-साथ सरगुन मेहता अपने स्टाइलिश और ग्लैमरस अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं। उनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है। फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार बैठते हैं। चाहे ट्रेडिशनल साड़ी हो, एलिगेंट सूट, ग्लैमरस गाउन या फिर कैजुअल वेस्टर्न आउटफिट, पंजाबी क्वीन हर लुक को बेहद खूबसूरती और कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करती हैं। सोशल मीडिया पर सरगुन की तस्वीरें छाई रहती हैं। फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। एथनिक आउटफिट में सरगुन की खूबसूरती देखते ही बनती है। साड़ी, लहंगा और अनारकली सूट में उनका एलिगेंट अंदाज फैंस को खूब पसंद आता है। वहीं, वेस्टर्न आउटफिट्स में भी वो अपने ग्लैमरस और मॉडर्न स्टाइल से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। मिनिमल मेकअप, स्टाइलिश हेयरस्टाइल और परफेक्ट एक्सेसरीज के साथ सरगुन हर बार अपने लुक को खास बना देती हैं। फैशन के साथ-साथ सरगुन की स्माइल और कॉन्फिडेंस भी उनके हर लुक में चार चांद लगा देते हैं। सरगुन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 9.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनके हर नए लुक का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। सरगुन भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करतीं और अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

सरगुन की सादगी और चार्म ही उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाता है। उनका फैशन सेंस भी काफी यूनिक है। इसमें कोई शक नहीं है कि सरगुन हर लुक में कहर ढाती हैं। स्टाइल स्टेटमेंट को लेकर भी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती हैं। कैरी ऑन जट्टा 4 की बात करें तो इस फिल्म के डायरेक्टर स्मीप कांग हैं। उन्होंने ही इस सुपरहिट पंजाबी कॉमेडी फ्रैंचाइजी के पिछली तीनों फिल्मों का निर्देशन किया है। फिल्म की कहानी नरेश कथूरिया ने लिखी है। गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता के अलावा इस फिल्म में बिन्नू ढिल्लों, पुखराज भल्ला, जैस्मीन बाजवा और गुरप्रीत घुग्गी जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं। गिप्पी ग्रेवाल और रवनीत कौर ग्रेवाल फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।

ट्रेंड को फॉलो नहीं करतीं अनन्या पांडे?

सेलिब्रिटी पर हमेशा ट्रेंड्स के साथ चलने का दबाव रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फैंस उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन पर ये दबाव इसलिए भी रहता है कि क्योंकि ब्यूटी ट्रेंड्स रातों-रात बदल जाते हैं। हालांकि अनन्या पांडे के लिए, आज खूबसूरती का मतलब ट्रेंड्स को फॉलो करना नहीं, बल्कि अपनी असलियत को अपनाना है। एक्ट्रेस ने बताया कि वह कभी भी ब्यूटी ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागतीं, बल्कि वही चीजें अपनाती हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से पसंद आती हैं।

कॉल मी बे की एक्ट्रेस ने कहा, मैं ट्रेंड्स को फॉलो वालों में से नहीं हूं। मुझे असल में ऑनलाइन सर्च करना पड़ता है कि अभी क्या ट्रेंड कर रहा है, वरना मुझे पता ही नहीं चलेगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरे लिए क्या सही है। अनन्या को फिल्म केसरी चैप्टर 2 और चांद मेरा दिल जैसी हालिया फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंस के लिए तारीफ मिली, हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाईं। सफलता और असफलता दोनों का अनुभव कर चुकीं यह एक्ट्रेस बड़े पर्दे के जादू में पक्का यकीन रखती हैं। अनन्या पांडे कहती हैं मुझे लगता है कि सिनेमा हमेशा रहेगा। मुझे थिएटर में जाकर हर तरह की फिल्में देखना पसंद है। मुझे सबसे ज्यादा मजा हर हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्में देखने में आता है। मेरे लिए, फिल्में देखना मेरे बड़े होने का एक अहम हिस्सा रहा है। मैं नई पीढ़ी को थिएटर जाकर फिल्में देखने और हमारे सिनेमा को जिंदा रखने के लिए प्रोत्साहित करूंगी।

सहायक प्रोफेसर भर्ती में पीएचडी, शोध और अनुभवी को मिले वेटेज

उत्तरकाशी(आरएनएस)। उत्तराखंड के राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में पीएचडी, शोध कार्य, शिक्षण अनुभव और अन्य अकादमिक उपलब्धियों को वेटेज देने की मांग अब सरकार तक पहुंच गई है। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रहित और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करने का आग्रह किया हैयह मांग शोधार्थियों और पीएचडी धारकों की ओर से विधायक को सौंपे गए ज्ञापन के बाद उठाई गई है।

उनका कहना है कि सहायक प्रोफेसर भर्ती में लिखित परीक्षा के साथ पीएचडी धारक अभ्यर्थियों की अकादमिक और शोध उपलब्धियों का भी पारदर्शी तरीके से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। शोधार्थियों ने सुझाव दिया है कि पीएचडी, नेट, शोध प्रकाशन, शिक्षण अनुभव और अन्य अकादमिक उपलब्धियों के लिए पहले से निर्धारित और पारदर्शी वेटेज तय किया जाए।भर्ती नियम यूजीसी रेगुलेशंस-2018 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की भावना के अनुरूप तैयार किए जाएं। यूजीसी की निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं को यथावत रखते हुए शोध एवं अकादमिक उपलब्धियों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए। शोध संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और महाविद्यालयों में अधिक योग्य शिक्षकों का चयन हो सकेगा।

एनआईटी में स्व-वित्तपोषित रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमएससी एवं एमटेक के स्व-वित्तपोषित (सेल्फ-स्पॉन्सर्ड) पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान ने पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।संस्थान के अनुसार सीसीएमएन-2026 के नेशनल स्पॉट राउंड (एनएसआर) के बाद एमएससी (भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं गणित) कार्यक्रमों में रिक्त सीटों पर स्व-वित्तपोषित प्रवेश दिए जाएंगे।

वहीं, सीसीएमटी-2026 के बाद रिक्त एमटेक सीटों के साथ-साथ 25 स्व-वित्तपोषित फुल-टाइम एमटेक सीटों पर भी प्रवेश होंगे। एमटेक के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभागों में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 4 अगस्त है। पात्र अभ्यर्थियों की सूची 6 अगस्त को संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर 10 अगस्त को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को 17 से 18 अगस्त के बीच संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। नए सत्र की कक्षाएं 9 अगस्त से शुरू होंगी। शुल्क, न्यूनतम पात्रता, सीटों का विवरण, आवेदन प्रक्रिया तथा अन्य आवश्यक जानकारी एनआईटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

सू- दोकू क्र.097

	7				1		3	
1		9				5		
			3				1	
		5						3
3					2		5	
				3				2
	4						7	
7		8		1		6		
	6		7		9			1

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.96 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में कई अहम फैसले, पिनाथ ईको ट्रेक के लिए 10 लाख मंजूर

अल्मोड़ा(आरएनएस)। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जनपद के पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटकों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विस्तार तथा विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी स्वीकृत कार्यों को गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए नगर क्षेत्र में दो सामुदायिक शौचालयों के निर्माण एवं विकास हेतु पांच-पांच लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा होटल एसोसिएशन अल्मोड़ा के अध्यक्ष अरुण वर्मा द्वारा प्रस्तुत पिनाथ ईको ट्रेक के विकास के प्रस्ताव को भी समिति ने मंजूरी दी। ट्रेक के विकास के लिए वन विभाग को 10 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस परियोजना के तहत आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे साहसिक और प्रकृति पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

बैठक में अल्मोड़ा नगर के ऐतिहासिक और प्राचीन बाजार के सौंदर्यीकरण पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर सौंदर्यीकरण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मल्ला महल कैफे एवं म्यूजियम के संचालन की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं शीघ्र पूरी कर संचालन शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मल्ला महल अल्मोड़ा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है तथा इसके संचालन से पर्यटक जिले की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सकेंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, प्रदीप धौलाखंडी, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा, होटल एसोसिएशन अल्मोड़ा के अध्यक्ष अरुण वर्मा, पार्षद अर्जुन बिष्ट, अमित साह सहित समिति के सदस्य और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

सरकारी अस्पताल में नए सर्जन ने संभाला कार्यभार

काशीपुर(आरएनएस)। एलडी भट्ट उप जिला चिकित्सालय में वरिष्ठ सर्जन डॉ. वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उनके आने से अस्पताल में अब दो सर्जनों की तैनाती हो गई है, जिससे सर्जिकल सेवाएं मजबूत होंगी। प्रभारी सीएमएस डॉ. वरुण भारद्वाज ने बताया कि इससे सामान्य व जटिल ऑपरेशन के साथ आपातकालीन सर्जरी भी बेहतर ढंग से हो सकेगी। मरीजों की ऑपरेशन के लिए प्रतीक्षा अवधि कम होगी और उन्हें स्थानीय स्तर पर बेहतर उपचार मिलेगा। हाल के दिनों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की बाहरी ड्यूटी के कारण प्रभावित सर्जिकल सेवाओं में भी अब सुधार की उम्मीद है।

खटीमा उप जिला चिकित्सालय को मिले छह नए चिकित्सक

रुद्रपुर(आरएनएस)। खटीमा उप जिला चिकित्सालय को छह नए चिकित्सक मिल गए हैं। सभी चिकित्सकों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। 15 दिन पहले अस्पताल के सात चिकित्सकों के स्थानांतरण के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो गई थीं, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। दो सामाजिक कार्यकर्ता दो दिन तक भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। जनभावनाओं को देखते हुए शासन ने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. वीपी सिंह के स्थानांतरण पर रोक लगा दी थी। शासन द्वारा सात चिकित्सकों के अचानक तबादले के बाद राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया था। इसके बाद एक चिकित्सक के तबादले पर रोक लगा दी गई थी।छह नए चिकित्सकों के कार्यभार ग्रहण करने से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती मिली है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. केसी पंत ने बताया कि महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. सीमा आर्या, डॉ. संजीव शर्मा, रेडियोलॉजिस्ट डॉ. जयहिंद सिंह, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. दिलीप वासडे, सर्जन डॉ. सचिन कुमार तथा डॉ. सुरेश अरोड़ा ने उप जिला चिकित्सालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नए चिकित्सकों के आने से स्वास्थ्य व्यवस्था के पटरी पर लौटने की उम्मीद है, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है।

बारिश से हुडोली-कंताड़ी मोटर मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त

उत्तरकाशी (आरएनएस)। मूसलाधार बारिश से हुडोली-पाणीगांव-कंताड़ी मोटर मार्ग को कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त कर दिया। दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह विभागीय जेसीबी की मदद से मार्ग को सुचारू किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि रातभर हुई बारिश के दौरान सड़क कई स्थानों पर धंस गई। पहाड़ी से लगातार मलबा और बड़े पत्थर गिरने से मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया जिससे सुबह तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। सूचना मिलते ही मंगलवार सुबह पीएमजीएसवाई ने जेसीबी मौके पर भेजी। मलबा हटाकर और चट्टानों की कटिंग कर अस्थायी रूप से सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया। हालांकि मार्ग पर लगातार भूस्खलन होने से सफर अब भी जोखिम भरा बना है।ग्रामीण दयाराम नेगी और बलबीर नेगी ने बताया कि पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने विभाग से क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवारों का जल्द पुनर्निर्माण, सड़क की स्थायी मरम्मत और संवेदनशील भूस्खलन स्थलों पर सुरक्षात्मक कार्य कराने की मांग की है। पीएमजीएसवाई के सहायक अभियंता सुभाष दोरियाल ने बताया कि मार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया गया है।

बहुउद्देशीय शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का किया निराकरण

नैनीताल (आरएनएस)। राज्य सरकार के सेवा, सुशासन एवं समर्पण अभियान के तहत बेतालघाट ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज लोहाली में जन कल्याणकारी एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। शुभारंभ विधायक सरिता आर्या व ब्लॉक प्रमुख अंकित साह ने किया। इस दौरान पेयजल, सड़क, सिंचाई, सीसी मार्ग, विद्युत, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़ी 42 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

शिविर में कृषि, उद्यान, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सहकारिता, राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, खाद्य, श्रम, उरेडा और रीप परियोजना समेत विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। विधायक सरिता आर्या ने कहा, कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति के घर के निकट तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जिन समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं हो सका, उनका शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग ने तीन महिलाओं को सीएम महालक्ष्मी किट दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने 50 से अधिक लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दा वितरित की।

14 वर्षीय बालिका को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीका लगाया गया। जनप्रतिनिधियों ने उल्गौर मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति, पुराने बिजली के पोल बदलने, गांवों में सोलर लाइट लगाने, सीसी एवं पैदल मार्गों की मरम्मत, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यालय भवन की छत की मरम्मत व गुलदार और बंदरों के आतंक से राहत दिलाने की मांग प्रमुखता से उठाई। विधायक सरिता आर्य ने वन विभाग को जल्द पिंजरा लगाने व संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ऊर्जा निगम के अधिकारियों के देर में पहुंचने पर नैनीताल विधायक ने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों पर कार्यवाही के आदेश दिए। यहां भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट, जिला उपाध्यक्ष रमेश सुयाल, ग्राम प्रधान निर्मला बिष्ट, उपप्रधान त्रिभुवन बिष्ट, तहसीलदार भुवन चंद्र भंडारी, डीडीओ संतोष पंत, बीडीओ पंकज जोशी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विश्वनाथ गौतम, सहायक परियोजना निदेशक चंद्रा फर्त्याल आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने एलआईयू निरीक्षक मनोज मनराल के निधन पर दुःख व्यक्त किया

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एलआईयू निरीक्षक मनोज मनराल के आकस्मिक निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन देहरादून में स्व. मनोज मनराल को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति एवं धैर्य प्रदान करने की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस दुःख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं।

कैंट क्षेत्र में जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण की मांग

संवाददाता

देहरादून। कैंट युवा समिति ने गढ़ी कैंट और टपकेश्वर क्षेत्र में लगातार लगने वाले यातायात जाम और सड़क पर बढ़ते दबाव को देखते हुए क्षेत्र की प्रमुख सड़कों का शीघ्र चौड़ीकरण कराने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि गढ़ी कैंट, डाकरा व टपकेश्वर क्षेत्र में आबादी तेजी से बढ़ने के कारण वाहनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सड़क संकरी होने से दिनभर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, मरीजों, गर्भवती महिलाओं तथा आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर राजन बस्नेत, शैलेन्द्र गुरूंग, पंकज क्षेत्री, गुरुदास तिवारी, राजेन्द्र कोर सौंधी सहित क्षेत्र के कई नागरिक शामिल थे।

एक और पेपर लीक!

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

इंजीनियरिंग, देहरादून को विश्वविद्यालय की सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों से अगले सात वर्षों के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग देहरादून को भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि संस्थान स्तर पर पर्याप्त निगरानी और नियंत्रण नहीं रखा गया, जिसके कारण इतनी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी शिक्षकों और संस्थानों को परीक्षा प्रणाली की गोपनीयता एवं शुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।

छात्रों के 'दर्द' पर सियासत का...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

तक सीमित नहीं रहने वाला। यहां राष्ट्रीय मुद्दों की सीधी टक्कर भी देखने को मिलेगी। दिल्ली का राजनीतिक तापमान अब देहरादून की सड़कों पर भी महसूस होगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सोशल मीडिया ने इस टकराव को और तीखा बना दिया है। हर दल अपने समर्थकों तक अपनी तस्वीरें पहुंचा रहा है। हर वीडियो का अपना राजनीतिक अर्थ निकाला जा रहा है। राजनीतिक दलों के लिए सड़क पर उतरना लोकतांत्रिक अधिकार है। विरोध करना भी अधिकार है। लेकिन विरोध तब सार्थक बनता है जब वह जनता के मुद्दों को केंद्र में रखे, न कि केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को घेरने का माध्यम बन जाए। यदि हर प्रदर्शन का अंत केवल नारे, धक्का-मुक्की और प्रेस बयान में होना है, तो लोकतंत्र की ऊर्जा धीरे-धीरे राजनीतिक प्रदर्शन में बदलने लगेगी। देहरादून की बैरिकेडिंग केवल दो दलों के बीच नहीं लगी थी। वह शायद उस दूरी का प्रतीक भी थी, जो राजनीति और जनता के वास्तविक सरोकारों के बीच लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ सत्ता अपने बचाव में है, दूसरी तरफ विपक्ष अपने हमले में। बीच में खड़ा नागरिक अब भी इंतजार कर रहा है कि कोई उसकी बात भी सुने। दिल्ली की लाठियों से शुरू हुई बहस देहरादून की सड़कों तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज हो सकता है। लेकिन लोकतंत्र की असली जीत तब होगी, जब राजनीतिक दल एक-दूसरे के मुख्यालय का घेराव करने से पहले उन सवालों का घेराव करेंगे जो वर्षों से उत्तराखंड और देश के युवाओं के सामने खड़े हैं। क्योंकि आखिर में इतिहास यह नहीं पूछता कि किसने किसका दफ्तर घेरा था। इतिहास यह पूछता है कि सत्ता और विपक्ष दोनों ने जनता के सवालों का जवाब दिया था या नहीं।

'डबल इंजन' के दावों पर 'युवा आक्रोश' भारी

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। राजनीति में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जो भाषणों से नहीं, तस्वीरों से चुनाव बदल देती हैं। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्रवाई, पेपर लीक को लेकर देशभर में उठे सवाल और उसके बाद विपक्ष की आक्रामक राजनीति ने उत्तराखंड की चुनावी बिसात पर भी नई चाल चल दी है। भाजपा ने शायद सोचा था कि 2027 का चुनाव विकास, डबल इंजन, निवेश, चारधाम और संगठन की मजबूती पर लड़ा जाएगा, लेकिन अचानक पूरा विमर्श बदलता दिखाई दे रहा है। अब चर्चा सड़कों की नहीं, चर्चा स्टार्टअप की नहीं,चर्चा निवेश की नहीं, चर्चा हैकृपेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य की और राजनीति का सबसे खतरनाक सच यही होता है कि जब जनता मुद्दा तय करने लगे, तब राजनीतिक दलों की रणनीतियां अक्सर बिखरने लगती हैं।

उत्तराखंड भाजपा पिछले कई महीनों से चुनावी मोड में दिखाई दे रही थी। बूथ समितियां सक्रिय थीं, लाभार्थी सम्मेलन चल रहे थे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिलों का दौरा कर रहे थे और संगठन चुनावी गणित मजबूत करने में जुटा था। लेकिन दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज और पेपर लीक की बहस ने अचानक पूरा राजनीतिक फोकस बदल दिया। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा युवा आखिर सोच क्या रहा है? क्योंकि उत्तराखंड का शायद ही कोई ऐसा गांव होगा, जहां कोई बेटा या बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी न कर रहा हो। यानी यह केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं यह हर घर का मुद्दा है।

कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी नैरेटिव में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। धरने,प्रदर्शन, प्रेस कान्फ्रेंस,सोशल मीडिया अभियान, हर मंच से एक ही संदेश युवाओं की लड़ाई अब कांग्रेस की लड़ाई है। राहुल गांधी लगातार छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर मुखर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि छात्र असंतोष को

◆पेपर लीक, छात्रों का गुस्सा और राहुल की सियासत
◆भाजपा के चुनावी रथ के सामने युवाओं की नाराजगी
◆दिल्ली में सड़कों से उठे छात्र आंदोलन से आया भूचाल

रोजगार, भर्ती और शिक्षा व्यवस्था से जोड़कर सरकार को कठघरे में खड़ा किया जाए। यही कारण है कि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में सवाल यह नहीं होता कि कौन राजनीति कर रहा है। सवाल यह होता है कि जनता किसकी बात सुन रही है।

उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय तक सड़क, पलायन, चारधाम, क्षेत्रीय अस्मिता और विकास के इर्द-गिर्द घूमती रही। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। हर भर्ती, हर परीक्षा,हर नियुक्ति अब केवल प्रशासनिक मामला नहीं रह गई है। वह सीधे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है। युवाओं के बीच यह धारणा बनी कि उनकी मेहनत का सम्मान नहीं हो रहा, तो इसका असर सीधे मतदान पर पड़ सकता है। यही भाजपा की सबसे बड़ी चिंता मानी जा रही है। चुनाव भाषणों से कम और माहौल से ज्यादा जीते जाते हैं। यदि विपक्ष यह माहौल बनाने में सफल हो गया कि सरकार युवाओं के सवालों से बच रही है, तो सत्ता के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि भाजपा अब केवल कांग्रेस का जवाब नहीं दे रही, बल्कि युवाओं तक यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि सरकार रोजगार, भर्ती और पारदर्शिता के मुद्दों पर गंभीर है। यानी चुनावी रणनीति के साथ-साथ डैमेज कंट्रोल भी शुरू हो चुका है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव केवल सरकार बनाम विपक्ष नहीं होगा। यह उम्मीद बनाम निराशा की लड़ाई भी हो सकती है। एक तरफ भाजपा विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस युवाओं की नाराजगी को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। अब देखना यह होगा कि जनता विकास के दावों पर भरोसा करती है या रोजगार के सवालों पर सरकार से जवाब मांगती है। राजनीति में सरकारें हमेशा विपक्ष से नहीं हारतीं। सरकारें तब मुश्किल में आती हैं, जब युवाओं की उम्मीदें सवाल बन जाती हैं। 2027 के चुनाव में शायद जनता नेताओं से यह नहीं पूछेगी कि कितनी सड़कें बनीं, बल्कि यह पूछेगी कि कितने युवाओं को नौकरी मिली? कितनी भर्तियां समय पर पूरी हुईं? पेपर लीक कब रुकेगा? यही वह सवाल हैं जो उत्तराखंड की चुनावी राजनीति का चेहरा बदल सकते हैं।

राज्यपाल से उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अध्यक्ष ने की शिष्टाचार भेंट

हमारे संवाददाता

देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) से आज लोक भवन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गजेन्द्र जोशी (से.नि.) ने शिष्टाचार भेंट की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट जनरल गजेन्द्र जोशी (से.नि.) को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनके नवीन दायित्व के लिए बधाई और सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

पीएम राहत योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: बर्द्धन

संवाददाता

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने पीएम राहत योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया।

सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को त्वरित एवं प्रभावी ट्रॉमा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्यों को जारी किए गए आदेशों के क्रम में मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने समन्वित, प्रभावी एवं समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापित किए जाने हेतु सम्बन्धित विभागों के साथ समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सभी आपातकालीन हेल्पलाईन सेवाओं को एकीकृत आपातकालीन हेल्पलाईन 112 से तकनीकी एवं परिचालानात्मक रूप से जोड़े जाने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए इसका आमजन तक

प्रचार-प्रसार किए जाने की बात भी कही। कहा कि सभी आपातकालीन हेल्पलाईनों का एकीकरण हो जाने के बाद हेल्पलाइन 112 पर पुलिस, फायर एवं मेडिकल सुविधा जैसी आपातकालीन सेवाएं तत्काल मिल सकेंगी। उन्होंने इसके लिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप वाला ऑटोमैटिक मैकेनिल्म तैयार किया जाने की बात भी कही, ताकि मेडिकल हेल्प, फायर या पुलिस सहायता के लिए 112 पर कॉल करने वाले व्यक्ति को वांछित सहायता तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

मुख्य सचिव ने कहा कि गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण तंत्र के लिए राज्य स्तर पर डीजी हेल्थ को नोडल आधिकारी एवं जनपद स्तर पर सीएमओ को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मासिक बैठकें आयोजित की जाएं एवं बैठकों का कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड किए जाएं। उन्होंने सभी सार्वजनिक एवं निजी एम्बुलेंसों में एआईएस-125 मानकों का अनुपालन एवं जीपीएस/वीएलटीडी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसकी प्रभावी निगरानी के लिए हेल्पलाईन 112 से रियल टाईम इंटीग्रेशन किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि ट्रॉमा रजिस्ट्री के लिए नोडल विभाग परिवहन विभाग होगा। उन्होंने परिवहन विभाग को राज्य स्तरीय ट्रॉमा रजिस्ट्री स्थापित करते हुए सभी चिकित्सा संस्थानों को इससे इंटीग्रेट किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसे राष्ट्रीय ट्रॉमा रजिस्ट्री से भी जोड़ा जाए। उन्होंने पीएम राहत योजना का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया। इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, रोहित मीणा, श्रीमती तृप्ति भट्ट एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

श्रमिक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: धामी

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रमिक और श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ योजना के अन्तर्गत 02 मेडिकल मोबाइल वैन का भी फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार श्रमिक कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज शुरु की जा रही कल्याणकारी योजनाएं भी श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि "मुख्यमंत्री पोषण योजना" के माध्यम से जहां श्रमिक परिवारों को पोषण सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं ष्मुख्यमंत्री शिक्षा सामग्री योजनाष के माध्यम से श्रमिक भाई -बहनों के बच्चों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक परिवारों के बच्चों को कौशल प्रदान करने के लिए शुरु की जा रही, मुख्यमंत्री योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना, के अंतर्गत पात्र छात्र-छात्राओं को योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत हर साल 210 बच्चों को आवासीय सुविधायुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए''श्रमेव जयते'' का मंत्र दिया था। इसी क्रम में राज्य सरकार भी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों को केवल श्रमशक्ति नहीं, बल्कि उत्तराखंड की विकासशक्ति मानती है। सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि जो हाथ प्रदेश के विकास का निर्माण करते हैं, उनका और उनके परिवार का जीवन भी सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध होना चाहिए। इसी सोच के तहत एक ओर राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं महिला श्रमिकों एवं श्रमिक परिवारों को मातृत्व के दौरान बेहतर देखभाल और पोषण के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रही है।

2028 तक यही रहेगा पैग का टाइम, तीन साल की नीति में तय हुए बार-ठेकों के घंटे

संवाददाता

देहरादून। वर्ष 2025-26 से लागू उत्तराखंड की तीन वर्षीय आबकारी नीति, जो 2027-28 तक प्रभावी रहेगी, के तहत बार और शराब दुकानों के संचालन का समय पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत आबकारी विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि पूरे नीति काल में यही समय लागू रहेगा।

बार का समय: सोमवार से शुक्रवार सुबह 11:00 बजे से रात 11:00 बजे तक। शनिवार और रविवार सुबह 11:00 बजे से रात 12:00 बजे (मध्यरात्रि) तक।

◆2025 से लागू आबकारी नीति में बार और शराब दुकानों के संचालन का समय पहले ही तय, 2028 तक इसी व्यवस्था पर चलेगा कारोबार

शराब के ठेकों का समय: देशी, विदेशी और मॉडल शॉप/रिटेल शराब दुकानें प्रतिदिन सुबह 9:00 बजे से रात 11:00 बजे तक। अंतर्राज्जीय सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुकानें रात 12:00 बजे तक खुल सकेंगी।

आरटीआई से मिली जानकारी में आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह समय-सारिणी 2025 में लागू हुई तीन वर्षीय आबकारी नीति का हिस्सा है और 2027-28 तक इसी व्यवस्था के तहत बार व शराब की दुकानों का संचालन किया जाएगा। निर्धारित समय से बाहर बिक्री या संचालन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

अनिल कुमार त्यागी बने मुख्य अग्निशमन अधिकारी

संवाददाता

हरिद्वार। फायर स्टेशन सिडकुल के फायर स्टेशन ऑफिसर अनिल कुमार त्यागी को पदोन्नत कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी बनाया गया है।

इस अवसर पर आयोजित समारोह में एसएसपी नवनीत सिंह ने अनिल कुमार त्यागी के कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें अलंकृत किया और उनकी इस पदोन्नति पर हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान अग्निशमन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ पदोन्नत अधिकारी के परिजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों में एमपी त्यागी, श्रीमती संतोष त्यागी, श्रीमती मध ु त्यागी, श्रीमती कल्पना त्यागी, नूपुर त्यागी, हिमांशु त्यागी, विशाल त्यागी और वैभव त्यागी ने अपनी गरिमामयी मौजूदगी दर्ज कराई। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं परिजनों ने अनिल कुमार त्यागी को पदोन्नति पर मंगलकामनाएं दीं और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं। उपस्थित सभी अधिकारियों एवं परिजनों ने अनिल कुमार त्यागी को फूल-मालाएं पहनाकर व मिठाई खिलाकर पदोन्नति की मंगलकामनाएं एवं शुभकामनाएं दीं।

सिनेमा कलाकार भी आए छात्रों के पक्ष में

संवाददाता

मुंबई। दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रही है। छात्रों के समर्थन में टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया के कई सितारें आगे आए हैं। श्अल्फाश एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी छात्रों को सपोर्ट किया है।

आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में आलिया ने लिखा कि पिछले कुछ दिनों ने बार-बार मेरा दिल तोड़ा है और फिर उम्मीद के साथ उसे जोड़ा भी है। अपनी बात पर डटे हर छात्र के पीछे एक सपना, एक परिवार की उम्मीद और अनगिनत त्याग का सफर छिपा है।

आलिया ने लिखा कि वो सिर्फ खुद का ही नहीं, बल्कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने उनका साथ दिया है और साथ ही वे आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर रास्ता भी बना रहे हैं। उनकी हिम्मत के आगे मैं नतमस्तक हूं। उनका संकल्प हम सबके लिए एक आईने की तरह है, जो हमसे पूछता है कि क्या हम सच में उन लोगों की बात सुन रहे हैं, जो इस देश के भविष्य के वारिस होंगे और इसे शेप देंगे?

गौरतलब है कि आलिया भट्ट के पहले भी की फिल्मी और टीवी स्टार्स ने छात्रों को सपोर्ट दिया है। सलमान खान, प्रकाश राज, शबाना आजमी जैसे सितारे इस आंदोलन में शामिल हुए। इनके अलावा सोनू सूद, वीर दास, दीया मिर्जा, सोहा अली खान, अदिति राव हैदरी, रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, राजकुमार राव, विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, भूमि पेडनेकर, हुमा कुरैशी, नंदिता दास, आयुष शर्मा, नसीरुद्दीन शाह, ऋतिक रोशन और स्क्रीनराइटर सुतापा सिकदर समेत कई अन्य लोगों ने ऑनलाइन पोस्ट शेयर कर सरकार से बातचीत करने की अपील की है।

बेरोजगार नर्सिंग एकता मंच का मुख्यमंत्री आवास कूच, गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार नर्सिंग एकता मंच ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया जिनको पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया जिसके बाद वह वहीं पर ध रने पर बैठ गये। जिसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया।

आज यहां बेरोजगार नर्सिंग एकता मंच के बैनर तले बेरोजगा नर्से परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए। जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। परेड ग्राउंड से राजपुर रोड, दिलाराम चौक होते हुए वह जैसे ही हाथीबडकला चौकी के पास पहुंचे पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको वहीं रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गयी। उनका कहना था कि सरकार को वर्षवार भर्ती करनी चाहिए। 12 साल बाद पेपर निकाली है। यहां पर भर्ती सिनियरटी के आधार पर होनी चाहिए। वह 12 साल तक इंतजार करते रहे और अब उनको इससे बाहर किया जा रहा है।

उनका कहना था कि एक तरफ तो सरकार बेटी बचाव, बेटी पढाओं का नारा दे रही है और दूसरी तरफ महिलाओ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। जहां एक ओर शिक्षित नर्सिग अधिकारी धरने पर बैठी है और सरकार सत्ता के अहंकार में डुबी हुई है। सरकार को पोर्टल को रद्द करना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा राज में युवाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले कई महीनों से वर्षवार भर्ती की मांग रहे बेरोजगार नर्सिग युवाओं को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सरकार का दायित्व है कि वह युवाओं की बात सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें और संवाद का रास्ता अपनाएं। धरने के पश्चात पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर उनको वापस धरना स्थल पर छोड दिया।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।